भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1793

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-कॉमर्स बाजार

1793. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता ई-कॉमर्स बाजार है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसमें वृद्धि और वार्षिक चक्रवृद्धि विकास-दर का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने देश में ई-कॉमर्स की भावी वृद्धि में बाधा डालने वाली किन्हीं समस्याओं की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा इन समस्याओं को दूर करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंत्रालय ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में ई-कॉमर्स की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): हाल के वर्षों में देश में ई-कॉमर्स क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसका मुख्य कारण डिजिटलीकरण को अपनाने में वृद्धि, बेहतर लॉजिस्टिक्स तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं एवं उद्यमों की व्यापक भागीदारी है। ई-कॉमर्स बाजार का विकास और समग्र वार्षिक वृद्धि के आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

इस क्षेत्र के विस्तार को उचित प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण, डेटा सुरक्षा एवं पारदर्शिता हेतु विकसित विनियामक फ्रेमवर्क द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो डिजिटल मार्केटप्लेस को प्रशासित करने वाले मौजूदा कानूनों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

देश में ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनेक हितधारक एवं प्रचालन मॉडल शामिल हैं, तथा इसके विस्तार के लिए स्थानीय खुदरा का अधिक एकीकरण, महानगरीय क्षेत्रों से आगे व्यापक पहुंच तथा छोटे विक्रेताओं, जिसमें, ग्रामीण एवं सेवाओं की पहुंच से बाहर के क्षेत्रों के विक्रेता भी शामिल हैं, की डिजिटल भागीदारी को अधिक सुगम बनाना आवश्यक है।

इन पहलुओं का समाधान करने हेतु, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पहल की शुरुआत की है। ओएनडीसी एक निष्पक्ष, अंतर-प्रचालन योग्य और ओपन नेटवर्क है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित छोटे विक्रेताओं को किसी एक स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निर्भरता के बिना डिजिटल कॉमर्स में भाग लेने में सक्षम बनाता है। ओएनडीसी, साइलो में काम करने वाले पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के विपरीत, एक ओपन ईकोसिस्टम बनाता है, जहां विक्रेता प्लेटफॉर्म-विशिष्ट नियमों और शर्तों की सीमाओं में बंधे बिना कई प्लेटफार्मों से ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ओएनडीसी यह सुनिश्चित करता है कि छोटे व्यवसाय, स्थानीय व्यापारी और एमएसएमई, उभरते हुए ई-कॉमर्स वातावरण के डिजिटल दायरे से बाहर न छूट जाएं और इन वर्गों को ई-कॉमर्स के परिवेश में ओपन प्रोटोकॉल के माध्यम से आकार, पैमाने तथा डिजिटल विशेषज्ञता के संदर्भ में निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण रूप से खोजे जाने के अवसर प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। ओएनडीसी ने छोटे और ग्रामीण विक्रेताओं के लिए अंतिम छोर तक आपूर्ति, भंडारण और पूर्ति विकल्पों को बेहतर बनाने के लिए कई लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी की है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), जिनमें ग्रामीण उद्यमी एवं कारीगर शामिल हैं, को अपने उत्पादों के विपणन एवं बिक्री हेतु ई-कॉमर्स अपनाने के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा, एमएसएमई टीम (ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग) पहल के माध्यम से "एमएसएमई उत्पादकता को बढ़ाना और इसे गति प्रदान करना

(आरएएमपी)" कार्यक्रम को सहायता प्रदान की जा रही है, जिसका उद्देश्य देशभर के एमएसएमई को ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने बाजार विस्तार हेतु सशक्त बनाना है। टीम स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई के परिचालन का डिजिटलीकरण किया जाता है तथा उन्हें सरकार समर्थित ओएनडीसी तक पहुंच प्रदान कर ऑनलाइन स्टोरफ्रंट, डिजिटल भुगतान एवं लॉजिस्टिक्स की सुविधा उपलब्ध कराते हुए ई-कॉमर्स अपनाने को बढ़ावा दिया जाता है; जिससे अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किए बिना सुगम ऑनबोर्डिंग एवं कैटेलॉगिंग संभव हो सके।

*****